

इस के ऊपर कालिग प्रेंटेशन दिया था। प्राज उन के मरने जीने का प्रश्न है। उन के लिए दवाइयाँ नहीं, पढ़ने के लिए किताबें नहीं, भोड़ने को कमल नहीं, रहने को मकान नहीं, कुछ भी उन के पास नहीं। ऐसी परिस्थिति के अन्दर क्या भारत सरकार केवल 200 रुपये साल में उनको मकान के लिए देकर शांत बैठ जायेगी? मैं निवेदन करूँगा कि सरकार उन के आवास की, उन के एजुकेशन की व्यवस्था करे और शीघ्रातिशीघ्र रिकवरी बन्द कर। मैं जानता हूँ केवल एक मंत्री महोदय का यह काम नहीं हो सकता। सारा मंत्रिमंडल बैठकर इस के ऊपर जल्दी निश्चय करे और निश्चय कर के उन्हें नागरिकता का अधिकार दे दे ताकि वे पशुवत जीवन न बिता कर भारत के अन्य नागरिकों की तरह अपने पुर्नर्वास से पूंजी कमा सकें और दयनीय दशा में न रहें।

(iv) SALE OF SEVERAL THOUSAND EAST
 PAKISTAN REFUGEE WOMEN FROM MANA
 CAMP

SHRI SAMAR GUHA (Contd.) :
 Sir, I want to draw the attention of the House through you to a very shocking and at the same time shameful affair that has been reported to the Chief Minister of West Bengal by a delegation of MLAs who were sent to Mana camp, Deoli camp and other different camps where the former East Pakistan refugees have been rotting for periods ranging from 7 to 15 years. Recently a group of MLAs was sent there to see the condition of the refugees in those camps. On the 17th, they and also 17 members of those refugee camps have made a representation to the Chief Minister of West Bengal wherein they have said that about 10,000 girls and women have been taken away from the Mana camp and other camps also and sold outside.

SHRI SHYAM NANDAN MISHRA (Begusarai) : What are the authorities doing?

SHRI SAMAR GUHA : There are serious complaints against the authorities. The girls and women have been subjected to shameful behaviour. There

are reports against the police also that some of the girls were taken away and atrocities committed on them. You will remember, I raised this matter of the rotting conditions in which the refugees live in different camps for 7 to 15 years. 1,30,000 former East Pakistan refugees have been kept by the Government deliberately in Mana and other camps, from where it is very difficult for them to come here and get any information whatsoever. They cannot come to the cities and make complaints. All kinds of reports against the employees and some other agencies are also coming again and again. The Minister for Rehabilitation is not here. I want to make a humble suggestion through you to the Minister that he may make a statement on this matter. The report has come out in Ananda Bazar Patrika of 18th December and it has been submitted by responsible persons who visited the camps. I would humbly request the minister to enquire into the matter about the behaviour meted out, by the government employees and also many other agencies working there to the refugees who have been kept in Mana camp, Deoli camp and other camps in Dandakaranya. An enquiry should be made and a report presented here. The conditions in which the refugees are living are almost at a sub-human level. A team of Members of Parliament should visit these refugee camps and make a report to the Government about their condition and also the policy in regard to their rehabilitation. These refugees who met the Chief Minister of West Bengal made an appeal that they want to go to Andamans. The other day when I raised the matter, the minister said, they will not be sent to Andamans. Almost every session I have been bringing this matter to the attention of the House. The Government promised that they will be sent to Andamans, but the Minister said the other day that they will not be sent to Andamans. The areas have been cleared there and these refugees want to go there. I would again humbly submit, let the minister make an enquiry about this report that has come out. Also, let him send a team of Members of Parliament to these refugee camps to see the conditions there and make a report and also submit a report about the policy and programme for their rehabilitation.

STATEMENT RE : APPOINTMENT BY
 INDIAN RED CROSS SOCIETY OF
 OFFICIALS ON A COMMITTEE TO
 DISTRIBUTE RELIEF MATERIALS

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री
 (श्री राजनारायण) : श्रीमान, 24 जून,

[श्री राज नारायण]

1977 को रैड-क्रास के सम्बन्ध में कुछ प्रश्न श्रीमती मुणाल गोरे ने यहां पर उठाये थे। इन का यह कहना सही है कि हम ने आश्वासन दिया था कि इस की जांच कराई जायेगी। अपने उस आश्वासन के मुताबिक हम ने जांच आरम्भ की और हम ने घर मंत्री को इस सम्बन्ध में लिखा कि सी० बी० आई० के द्वारा इस की जांच कराई जाए। सी० बी० आई० के अधिकारी गये लेकिन अन्त में सी० बी० आई० के अधिकारियों ने मुझ को यह सूचित किया कि क्योंकि यह एक अन्तर्राष्ट्रीय संस्था है, इसलिए इस की इन्क्वायरी सी० बी० आई० के द्वारा नहीं की जा सकती। फिर हम ने घर मंत्री को कहा कि आखिर इस की जांच की कोई न कोई व्यवस्था होनी चाहिए। सी० बी० आई० और अन्य लोगों ने कहा कि इंटेलेजेन्स ब्यूरो के जरिये जांच कराई जा सकती है। उस में भी थोड़ा विलम्ब हुआ। तो हम ने एक और रास्ता निकाला कि कम से कम हमारा स्वास्थ्य विभाग, जितना रुपया उस ने रैड क्रॉस को दिया है, उस रुपये की तो इन्क्वायरी करा ही सकता है। उस इन्क्वायरी को करते समय जो चीजें मिल जाएंगी, तो इस सम्बन्ध में और ज्यादा चीजें बढ़ जाएंगी। तो सदन को जो मैंने आश्वासन दिया था, इन रिपोर्ट हम ने उस के मुताबिक तत्कालीन कदम उठाए थे, यह मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं।

श्री स्वाम नम्बन मिश्र (बेगुसराय) : अब इस में आप क्या कर रहे हैं।

श्री राज नारायण : उसी पर मैं था रहा हूं। क्या इन के प्रश्न थे। एक तो इन का प्रश्न यह था कि जो इन्क्वायरी की बात की गई थी, उसमें फरदर कार्यवाही क्या हुई। फरदर कार्यवाही यह हुई कि जो रैडक्रॉस के चैयरमैन थे, वे जो अन्तर्राष्ट्रीय रैडक्रॉस सम्मेलन हो रहा था, मुल्कों का, उस में चले गये थे। इसलिए इस में थोड़ा सा विलम्ब

हुआ उन के वहां रहने से। जब वे वहां से लौट कर आए, तो उन की तरफ से यह धाफर आया कि वे स्वतः जांच कराने के लिए तैयार हैं और जांच होने के बाद यह पाया गया कि रैड क्रॉस की तीन कारें हैं, डी०एच० ई० 8658, डी० एच० बी० 6141 और डी० एच० सी० 8295। इन का कहना था कि इन पर से रैडक्रॉस का चिन्ह हटा दिया गया। मंगाया गया था रैड क्रॉस का कह कर ताकि कस्टम ह्यूटी खत्म हो जाए मगर बाद में रैड क्रॉस का चिन्ह हटा दिया गया और वे पर्सनल स्टाफ कार की तरह से इस्तेमाल की जाने लगीं। एक तो यह चार्ज था।

दूसरा कहना यह है कि कुछ रेलवेज ने रैड क्रॉस वालों को इधर उधर घाने जाने की सज़ाविलयें दी हैं और उस में उन्होंने उन का काफी दुरुपयोग किया है। तो हम ने रेलवे मंत्री जी से रिक्वेस्ट की है कि वे इस की जांच कर लें कि इसमें कुछ दुरुपयोग हुआ है या नहीं। उस की जानकारी जब रेल मंत्रालय से मिलेगी, तो माननीय सदस्या और सदन को दे दी जाएगी।

अवली बास यह भी कि स्टेट बैंक के 8 बैंक 52,000 रुपये के बिदडा कर लिये गये और जो रुपया बिदडा किया गया और इन का कहना था कि वह ठीक ढंग से नहीं हुआ है। इस के लोकनेट्स भी गायब हैं।

चौथा प्रश्न जो आज का था, वह यह था कि प्रांथ प्रदेश के लिए जो रिलीफ कमेटी गई है, उन में कुछ ऐसे लोग हैं जिन के ऊपर पहले से आरोप थे जबकि बंगला देश के समय रैड क्रॉस के जरिये माल भेजा गया था और जिस की बाजार में बहुत शीहरत हुई थी। वह गलत ढंग से बेचा गया था और उस को बेच कर धन कमाया गया था। उनके बारे में इनका कहना था कि ऐसे लोग भी वहां पर गये थे क्या? इस बारे में हमारा कहना यह है कि 26 तारीख को हमारे स्टेट मिनिस्ट

धौर एडीशनल सेक्रेटरी वहां जा रहे हैं जो जा कर के जांच करेंगे कि सचमुच में उनके जरिये से माल का वितरण हो रहा है या नहीं ।

श्री वसंत साठे (प्रकोला): मैं यह जानना चाहता हूँ कि आपने जो जांच करायी है, क्या आपको मालूम है कि अन्तर्राष्ट्रीय संस्था जो रेडक्रास की है, उसने, खास कर बंगला देश में जो रेडक्रास का मामला हुआ, उस प्रकरण के बारे में उस अन्तर्राष्ट्रीय संस्था ने जांच करा कर आपको एक खत लिखा कि उन्होंने इस सम्बन्ध में जांच करायी है और उन्हें संतोष है कि कोई दुरुपयोग भारतीय रेडक्रास द्वारा नहीं हुआ है । क्या आपने वह खत देखा है ?

श्री राज नारायण : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा था कि हमारे स्टेट मिनिस्टर जा रहे हैं, एडीशनल सेक्रेटरी जा रहे हैं । वे जा कर यह जांच करेंगे कि ब्रांध्र में, तामिलनाडु में, केरल में, रेडक्रास का जो माल गया है उसका समुचित रूप में वितरण हुआ है या नहीं ।

हमने एक अहतिवादी कार्यवाही कर ली है कि ब्रांध्र प्रदेश में जो रेडक्रास सोसायटी है वह स्वतः उस माल को वितरित करे जो माल यहां से जाए । यह उसकी जिम्मेदारी होगी ।

एक प्रश्न आया कि क्या हम स्टेट सर्वन-मेंट के जरिये से मदद कर रहे हैं या नहीं ? जितनी भी मदद ब्रांध्र ने मांगी, केरल ने मांगी, तामिलनाडु ने मांगी, वह सारी की मारी मदद भारत सरकार के स्वास्थ्य विभाग के मेडिकल स्टोर भारगेनाइजेशन द्वारा दी गयी । इस भारगेनाइजेशन द्वारा ब्रांध्र प्रदेश को 35 लाख, 9 हजार, 375 रुपये के मूल्य की रोगनाशी, कीटनाशी और बैक्टीरिआ दवाइयां भेजी गयीं । इसी भारगेनाइजेशन द्वारा अन्य राज्यों की भी

दवाइयां भेजी गयीं जो कि तूफान से पीड़ित थे । इनका विवरण इस प्रकार है । तामिलनाडु 5 लाख, 61 हजार, 625 रुपये की दवाएं भुगतान ब्रांध्र पर, लसद्वीप को 94,525 रुपये की दवाएं भुगतान ब्रांध्र पर भेजी गयीं । केरल को हैजा नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत 25 हजार रुपये की दवाएं मुफ्त भेजी गयीं । जितनी भी मदद राज्य सरकारों ने हम से मांगी, वह सब हमने भेजी है । अब इनके सवालों में जो चौथी सवाल है....

श्री वसंत साठे : लेकिन जो करण्ट लोगों को दी गयीं ?

श्रीमती मृणाल गोरे (बम्बई उत्तर): मेरा जो करण्ट लोगों के लिए चार्ज है उसके बारे में आप बताएं ।

उपाध्यक्ष महोदय : उसके बारे में कहा है कि जांच की जा रही है ।

श्री राज नारायण : ब्रांध्र प्रदेश रेडक्रास सोसायटी ब्राजकल वही इस सारे माल को वितरित कर रही है ।

श्रीमती मृणाल गोरे : क्या आप स्वतंत्र रूप से इस सब की जांच करायेंगे, इसका जवाब मुझे चाहिए ? वह जवाब दिया जाए ।

श्री राज नारायण : वहां जो मेनेजिंग बाडी है इंडियन रेडक्रास सोसायटी की, उसने एक जांच बिठायी है । श्री सुबिमल दत्त जो कि पहले विदेश सचिव थे और भूतपूर्व केन्द्रीय बिजिलेंस कमिशनर भी रह चुके हैं, उन्होंने के अधीन यह जांच हो रही है । माननीय सदस्या को इस जांच से संतोष नहीं है । उनका तर्क है कि जिस मेनेजिंग बाडी के विरुद्ध आरोप है उसी मेनेजिंग कमेटी द्वारा जांच क्यों बिठायी गयी ? मैं सम्मानित सदस्या को इस अवसर पर इतना कहना चाहता हूँ । अगर श्री दत्त की जांच

[श्री राज नारायण]

के बाद कोई ऐसी स्थिति रहती है कि धीर जांच कराने की आवश्यकता है तो धीर जांच करा ली जाएगी धीर छोड़ा नहीं जाएगा। उनके इस प्वाइंट में लाजिक है, तर्क है कि जिस के बिना शिकायत हो वही जांच क्यों बिठाए। इस बात को मैं प्रधान मंत्री जी तथा धीर सब लोगों को बता दूंगा। सम्मानित सदस्या के धन्यवाद जो भाव है धीर सम्मानित सदस्यों के जो भाव है...

श्री बसन्त साठे : दत्त साहब को यहां की प्रोसीडिग्स भेज दें।

श्री राज नारायण : भेज दी जाएगी। प्रधान मंत्री, पूरी सरकार को इसकी जानकारी करा दी जाएगी ताकि कोई लेक्यूना न रहे।

हमें किसी पद का तात्पर्य नहीं है। धन्यवाद देने के पालन में हमें फोर्मेसिली यह मालूम हो जाएगा कि बाधा पड़ रही है तो पद को किसी भी ढंग हम छोड़ सकते हैं...

श्री बसन्त साठे : किस को धन्यवाद दे रहे हैं?

श्री राज नारायण : उनको धन्यवाद देता हूँ।

श्री बसन्त साठे : हटने से उनको क्या सन्तोष हो जाएगा?

श्री राज नारायण : उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ ताकि उनके मन में शंका न रहे कि हमारे धीर मैनेजिंग बोर्ड के चेयरमैन के बीच में कोई सांठगांठ हो गई है धीर सांठगांठ के जरिये ऐसी चीज हुई है। इसको कृपा करके वह धन्यवाद मन से निकाल दें। हम दुसरी चलाने वाले नहीं हैं, हम सीधे चलने वाले हैं, स्टेटफार्म हैं, जो सोचेंगे वही करेंगे जो कहेंगे वही करेंगे।

14:15 hrs.

RESOLUTION RE. FIRST REPORT OF THE RAILWAY CONVENTION COMMITTEE

THE MINISTER OF RAILWAYS -1 (PROF. MADHU DANDAVATE) : Sir, I beg to move :

"That this House approves the recommendations made in paras 5, 6, 7, 11, 14, 17 and 18 contained in the First Report of the Committee appointed to review the rate of dividend payable by the Railway undertaking to General Revenues as well as other ancillary matters in connection with the Railway Finance and General Finance which was presented to Parliament on the 17th November, 1977.

That this House further directs that the action taken by Government on the recommendations made in this Report, should be reported to the Committee".

Sir, by a resolution passed by Parliament on the 15th January, 1976 in the Fifth Lok Sabha and on 20-1-76 in the Rajya Sabha, the recommendations contained in paras 4, 5, 15, 16, 17 and 23 of the Eleventh Report of the Railway Convention Committee, constituted in 1973, in the matter of dividend payable by the Railway undertaking to General Revenues as well as ancillary matters in connection with the Railway Finance and General Finance, were approved by Parliament with the further direction that the action taken by the Government on the other recommendations made in that Report, as well as in the Eighth and Ninth Reports, should be reported to the said Committee. The action taken on these reports has been duly advised to that Committee.

The recommendations made in the Eleventh Report of the Railway Convention Committee, as approved by Parliament, determined the rate of dividend payable by the Railway undertaking to General Revenues and other ancillary matters in respect of the financial year 1976-77.

With the dissolution of the Fifth Lok Sabha, the Railway Convention Committee constituted in 1973 became *functus officio*. On the constitution of the Sixth Lok Sabha, a resolution was passed by this House on 2nd August, 1977 and by the Rajya Sabha on 4th August, 1977 constituting a new Railway Convention Committee, consisting of 12 members from the Lok Sabha and 6 members from the Rajya Sabha. As the recommendations of this Committee in the matter of dividend payable by the Railway undertaking to General Revenues and other